श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल का कोविड सेंटर बंद होने की कगार पर, दो डॉक्टरों, कुछ स्टाफ को हटाया गया

प्रशासक को फिर तीन महीने राजनीति करने का लाइसेंस मिला

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल तिकोना पार्क में खोला गया कोविड सेंटर अब मरणासन्न हालत में जा पहुंचा है। अस्पताल के दोनों डॉक्टरों और कई स्टाफ से आने को मना कर दिया गया है। कोविड सेंटर को बंद कर यहां ओपीडी शुरू कराने की कोशिश जारी है। इस बीच फरीदाबाद के सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि श्रीराम अस्पताल से उनका कोई संबंध नहीं है। न ही उन्होंने इस अस्पताल को बंद कराया था और न ही इसे खुलवाया था। उधर, नियम तोड़कर यहां रखे गए रजिस्ट्रार सोसायटीज के प्रशासक को फिर से तीन महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, जबकि उसे जो मूल काम सौंपा गया था, उसमें वो कोई तीर नहीं मार सका है।

कंधों का सहारा लेकर खुला कोविड सेंटर कब तक

श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल में घुसने के लिए कंधों का सहारा लेकर खोले गए कोविड सेंटर की असलियत अब सामने आ रही है। आज की तारीख में इस कोविड सेंटर में एक भी कोविड मरीज भर्ती नहीं है। इस सेंटर को कभी भी बंद किया जा सकता है। इसे खोले जाने के बाद श्रीराम धर्मार्थ चेरिटेबल सोसायटी के निलंबित प्रधान कंवल खत्री ने खुद मजदूर मोर्चा को बताया था कि अब तक 11 लाख रुपये इसे शुरू करने पर खर्च हो चुके हैं लेकिन मरीज कुल पांच आए।

मरीज न आने की वजह से यहां रखे गए दोनों डॉक्टरों को अब न आने के लिए कहा गया है। यानी अस्पताल सैलरी नहीं दे पाएगा। इसी तरह अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या भी कम कर दी गई है। स्टाफ को सैलरी न दे पाने की वजह से यह स्थिति पहुंची है। यही वजह है कि अब यहां ओपीडी शुरू करने के लिए दांवपेंच चलाए जा रहे हैं। भाजपा विधायक सीमा त्रिखा की वजह से यहां आरएसएस के पदाधिकारी गंगाशंकर ने यहां आकर कई घोषणाएं मीडिया के सामने कीं। उन्होंने कहा कि यहां पर भारत विकास परिषद और अन्य संगठन सहयोग करेंगे। फिर इन लोगों ने आईएमए से अनुरोध कर कंसनट्रेटर दिलवाए, जो आज तक इस्तेमाल नहीं हो सके। आईएमए के पास अभी भी अन्य जगहों से कंसनट्रेटर की मांग आ रही है, जहां कोरोना मरीज भर्ती हो रहे हैं। लेकिन राजनीतिक कारणों से आईएमए श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल से वो कंसनट्रेटर वापस नहीं मांग रहा, जबकि अन्य जगहों से मांग आई हुई है।

निलंबित प्रधान कंवल खत्री के अनुरोध पर विधायक सीमा त्रिखा और संघ के गंगाशंकर यहां ओपीडी चलवाने के लिए डीसी से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसमें कानूनी पेंच फंस रहा है। कोविड सेंटर तो एक महामारी की वजह से यहां खोला गया लेकिन ओपीडी खोलने का आधार महामारी को बनाया नहीं जा सकता। इसका तोड़ निकालने के लिए यह गुट रात-दिन विचार कर रहा है लेकिन कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा। श्रीराम चेरिटेबल सोसायटी में विवाद के बाद इस अस्पताल पर ताला लगा था। जब तक वो विवाद खत्म नहीं होता, यहां पर ओपीडी का चलना आसान नहीं है। कोई भी पक्ष उसे रजिस्ट्रार सोसायटीज और अदालत में चुनौती दे सकता है।

रजिस्ट्रार फरीदाबाद ने प्रशासक को यहां सोसायटी का विवाद हल करने के लिए भेजा था। उसे यह काम तीन महीने में करना था। लेकिन उसने कंवल खत्री गुट के साथ मिलीभगत करके यहां कोविड सेंटर खुलवा दिया। विवाद सुलझाने की दिशा में उसने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब उसका कार्यकाल इस सोसायटी में तीन महीने के लिए और बढ़ गया है। दरअसल, सोसायटियों में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासकों को हर महीने सैलरी और भत्ता मिलता है। फिर जिस ग्रुप से वो मिल जाता है, वहां से भी अपना जुगाड़पानी कर लेता है। रजिस्ट्रार सोसायटीज फरीदाबाद को 7 जून को तमाम अनियमितताओं की वजह से हरियाणा सरकार ने निलंबित कर दिया लेकिन उसने उसी दिन श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल के प्रशासक का कार्यकाल गैरकानूनी ढंग से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। उस प्रशासक ने कोविड सेंटर चलाने के नाम पर बैंक में रखी गई सोसायटी की एफडी पर लोन तक ले लिया, जिसका उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पूर्व रजिस्ट्रार ने इस प्रशासक के सामने सोसायटी के दूसरे गुट के सामने स्वीकार किया था कि उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, जिसमें वो सुधार करेंगे। लेकिन रहस्यमय कारणों से उन गलतियों को सुधारने की जगह प्रशासक फिर से एक्सटेंशन ले गया। सोसायटी का दूसरा गुट अब खुलकर इस प्रशासक पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है।

सीएमओ का भी इस्तेमाल

कोविड सेंटर खोले जाने के मौके पर तमाम लोगों की भीड़ कंवल खत्री गुट ने यहां जुटाई थी। जिसमें सीएमओ फरीदाबाद भी शामिल थे। सीएमओ को यहां भाजपा विधायक सीमा त्रिखा की वजह से आना पड़ा था। लेकिन सीएमओ ने अब लिखित रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इस संबंध में सीएमओ ने जवाब दिया है कि उनका श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल खोले जाने या बंद कराए जाने के मामले से कुछ भी लेनादेना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह नहीं लिखा है कि वो भाजपा विधायक के बुलावे पर कार्यक्रम में गए थे लेकिन सरकारी अधिकारी की स्थिति को समझा जा सकता है।

घपलेबाजी के आरोप पर चुप्पी

श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल के शव वाहन के लिए सुकृत सेवा मंडल की जिन पर्चियों का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे वसूले गए, उस पर कंवल खत्री गुट ने चुप्पी साध ली है। हालांकि मजदूर मोर्चा में खबर छपने के बाद इस गंभीर आरोप पर कंवल खत्री ने अपने खास लोगों से सुकृत सेवा मंडल के नाम पर पर्ची न काटने को कहा है। जिन लोगों के पास पर्चियां थीं, उनसे वापस भी मांगी जा रही है। लेकिन इस गुट ने अभी तक पंजाबी बिरादरी के सामने यह सफाई पेश नहीं की है कि आखिर अमानत में खयानत क्यों की गई। यहां तक उसने सुकृत सेवा मंडल की पर्चियों को लेकर मजदूर मोर्चा की खबर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसका सीधा सा अर्थ है कि सुकृत सेवा मंडल की पर्चियां काट कर कमाई की गई है, बेशक वो पैसा शव वाहन के ही नाम पर क्यों न आए।

कभी एलएमएस तो कभी डोंगल के नाम पर छात्र फंड का दुरुपयोग करते शिक्षा विभाग के अफ़सर

फरीदाबाद, (म.मो.): हरियाणा शिक्षा विभाग में छात्र फंड के दुरूपयोग के नित नये मामले सामने आ रहे हैं। डिजिटल क्लास के नाम पर एक कंपनी को एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) नामक एक कम्प्यूटर प्रोग्राम के लिये करोड़ों रुपये लुटने पर पहले ही बवाल मचा हुआ है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज लगाने के लिये अफ़सरों ने एक कंपनी को ठेका दिया था। जिसके लिये फ़रमान जारी करके कॉलेजों से इस कंपनी को करोड़ों रुपये की पेमेंट करने को कहा गया। और शर्मनाक बात ये है कि अफ़सरों ने ये पेमेंट कॉलेज में जमा छात्र फ़ंड में से करने को कहा जो कि न सिर्फ़ नियम विरुद्ध है बल्कि छात्रों के साथ अन्याय भी है। छात्रों को कुछ देना तो दूर उनसे वसूली फ़ीस भी खा-पी ली गई। इस पर जब कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने सवाल उठाये और कई प्रिंसिपलों ने इस नियम विरुद्ध पेमेंट पर स्पष्टीकरण मांगा तो शिक्षामंत्री ने अब इसकी जांच करवाने का आश्वासन दिया है।

बता दें कि कहने को तो छात्राओं के लिये हरियाणा में शिक्षा बिल्कुल फ्री है, और छात्रों से मामूली फ़ीस ली जाती है लेकिन विभिन्न फंडों के नाम से यहां मोटी वसूली की जाती है। इन्हीं में से एक है कंप्यूटर फंड। कंप्यूटर की शिक्षा देने के नाम पर बीए (प्रथम वर्ष) के छात्रों से 900 रुपये सिर्फ़ एक साल और बीसीए व बीएमए के छात्रों से 1200 रु. हर साल वसूले जाते हैं। बड़े कॉलेजों में यह फ़ीस हर साल करोड़ों रुपये तक जमा हो जाती है। भ्रष्ट अफ़सरों और मंत्रियों, संतरियों की लार इसी मोटी रकम पर टपकती रहती है। इस फंड को हड़पने की पहली साजिश तो 2019 में 'डोंगल' पेमेंट करने में की गयी और दूसरी अब एलएमएस के नाम पर। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज लगाने के नाम पर शिक्षा विभाग ने एलएमएस नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिये एक कंपनी को ठेका दे दिया। यहां यह बता देना उचित होगा कि गूगल पर 'गूगल क्लासेज' नाम से एक फ्री सॉफ्टवेयर पहले ही उपलब्ध है जिसका उपयोग फ्री में किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर या उस कंपनी के प्रोग्राम से बेहतर है क्योंकि उसमें छात्रों की हाजिरी लगाने समेत कई अन्य सुविधायें भी उपलब्ध है। लेकिन फ़िर भी इसका उपयोग न करके एक कंपनी को एक नये सॉफ्टवेयर के लिये ठेका देना क्या अफ़सरों की नीयत पर सवाल नहीं खड़े करता?

हर कॉलेज को इस साफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिये टैक्स समेत 2 लाख 90 हजार रुपये देने हैं। इस साल लगभग 200 कॉलेज में इसको लागू करने का फ़रमान है, जिससे कंपनी को लगभग पांच करोड़ रुपये हासिल होंगे।

जिसकी पेमेंट 'छात्र कंप्यूटर फंड' से दी जायेगी। जिसे कोई भी बता सकता है कि यह सारा ड्रामा के ऊपर मोटी रिश्वतखोरी के बिना नहीं खेला गया होगा। दुख की बात यह है कि लॉकडाउन और बेरोजगारी की मार से त्रस्त गरीबों के बच्चों के पास न तो कोई स्मार्ट फ़ोन था और न ही ज्यादातर कॉलेजों में 'ऑनलाइन कॉलेज' के लिये कोई टीचर था। फिर भी उनकी क्लास लगाने के नाम पर उन्हीं के पैसे की लूट जारी थी। अगर बच्चों की पढाई की चिन्ता थी तो सबसे पहले पूरा स्टाफ़ ही भर्ती कर लेते।

इससे भी पहले 2019 में ऑनलाइन के नाम पर एक और भी तमाशा हो चुका है जो इन शातिर दिमाग अफ़सरों की रिश्वतखोरी की दास्तान कह रहा है। बताया जाता है कि 2019 से उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी प्राध्यापकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन भरने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि इसके लिये सरकार के 'एचआर-एमएस' पोर्टल पर आसानी से इसका इन्तजाम किया जा सकता था जिसमें कोई अलग से खर्चा नहीं आता। लेकिन इसकी बजाय सरकार यानी शिक्षा विभाग के अफ़सरों ने निर्णय लिया कि सभी प्राध्यापक अपनी गोपनीय रिपोर्ट में 'डिजिटल सिग्नेचर' से हस्ताक्षर करेंगे जिसके लिये उन्हें एक डोंगल दिया जायेगा। 'डोंगल' एक प्रोग्रामयुक्त पेन ड्राइव है जिसे इस्तेमाल कर आप अपना कोई भी दस्तावेज प्रमाणित कर के भेज सकते हैं। ये 'डोंगल' बनाने का ठेका ऊपर से ही एक कंपनी को दिया गया जिसके लिये उसे प्रति व्यक्ति 2700 रुपये का भुगतान किया गया। ये 2700 रुपये ऊपर के निर्देशों के अनुसार छात्रों के कंप्यूटर फंड में से दिये गये। बाजार में इस तरह के 'डोंगल' की कीमत 2000 रुपये है। स्पष्ट है कि इस फालतू काम के लिये कंपनी को लगभग 80 लाख रुपये (कुल प्राध्यापकों की संख्या अनुमानित 3000 हैं।) का भुगतान किया गया जो कि बाजार में 60 लाख रुपये में हो सकता था। (हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं थी।) इस 'डिजिटल सिग्नेचर' का हर दो साल में नवीकरण किया जाना है जिसकी फ़ीस 1000 रुपये है। तो जाहिर है कि इस साल भी नवीकरण के नाम पर कंपनी को 30 लाख रुपये की फ़ीस और दी जायेगी।

लेकिन अब जब कुछ प्रबुद्ध अध्यापकों व प्रिंसिपलों द्वारा इस छात्र फंड के दुरूपयोग या लूट? के खिलाफ़ आवाज उठाई गई तो सफ़ाई दी जा रही है कि इस बार नवीनीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि विभागीय पोर्टल में अब इसका प्रावधान कर दिया गया है। छात्रों के कंप्यूटर फंड से निकाला पैसा भी वापिस करने का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या उन अफ़सरों के खिलाफ़ कुछ कार्रवाई होगी जो ऐसी तिकड़में भिड़ा कर छात्रों और जनता के पैसे को हड़पते रहते हैं। क्या उनकी तनख्वाह से ये पैसा वसूल किया जायेगा? बिल्कुल नहीं किया जायेगा क्योंकि यह लूट अकेले अफ़सर नहीं डकार रहे, इसमें मोटा हिस्सा तो शिक्षामंत्री का रहता है।

जब आधे से ज्यादा कॉलेजों और स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं, दफ्तरी स्टाफ़ नहीं, बिजली पानी व शौचालयों की सुविधा नहीं, टीचर नहीं तब डिजिटल और कंप्यूटर के नाम पर कभी 'एजूसेट', कभी 'कंप्यूटर लैब' कभी 'एलएमएस' तो कभी 'डिजिटल सिग्नेचर' जैसे झुनझुने पकड़ाना सिर्फ़ कमीशनखोरी का एक जरिया ही बन के रह जायेगा।

अगर वास्तव में लोगों को शिक्षित करना है तो पहले सामाजिक माहौल ठीक कीजिए, फ़िर स्कूलों और कॉलेजों के भवन बनाइये, पूरा स्टाफ़ भर्ती कीजिये, और फ़िर कॉलेजों स्कूलों में छात्रों, अध्यापकों और बुद्धिजीवियों के बीच बहस मुबाहसा करके नये शिक्षा के रास्ते खोजिये। लेकिन इस पर पैसा खर्च होगा, जो वर्तमान में मूर्तियों और मंदिरों पर खर्च किया जा रहा है।

व्यंग्य राजनैतिक चेहरा

अनिल हसानी

पार्टी अध्यक्ष- "अरे राज्य में चुनाव आने वाले हैं, जल्दी से कोई बढ़िया चेहरा दिखाओ वोट खींचने वाला।"

दुकानदार- "क्या दिखाऊ साहब। ब्राह्मण चेहरा, दलित चेहरा, अल्पसंख्यक चेहरा सब है अपने पास। आप बस आदेश करें।"

"यार अभी तो कोई अच्छा ब्राह्मण चेहरा दिखाओ, अपने पास स्टॉक में एक भी ढंग का ब्राह्मण नही है।"

"अच्छी बात है सर, ब्राह्मण दिख देता हूँ। किस पार्टी का पसंद करेंगे कांग्रेस, सपा या बसपा का? बसपा में कुछ ताजा स्टॉक हैं ब्राह्मणों का एकदम unused नए जैसा।"

"अरे ये सपा बसपा वाला अपने को जमेगा नही, कांग्रेस का दिखा दो आप तो, आराम से एडजस्ट हो जाएगा।"

"ठीक है तो फिर आप इस प्रसाद को ले जाओ, निराश नही करेगा।"

"ले तो जाए पर लंबा चलेगा न? पिछली बार 2014 मे एक दलित चेहरा आपसे ही ले गए थे, उसने 2019 में धोखा दे दिया था।"

"अब साहब हम दो साल की वारंटी दे सकते हैं। उसके बाद पार्टी जैसा मेंटेन करेगी वैसा चलेगा। ज्यादा सर पर भी मत चढ़ाना MP वाले महाराज चेहरे की तरह। खैर ये महाराज जितना मेंटेनेंस नही मांगता।"

"ठीक है, फिर इसे ही पैक कर दो।"

"कोई अल्पसंख्यक चेहरा दिखाऊं क्या वोट काटने के लिए?"

"नही, उसकी जरूरत नही, उसके लिए हमारे पास एक ओवैसी काफी है।

जायदाद से बेदखली की सूचना

मैं जय किशन पुत्र स्व. गिर्राज चन्द निवासी रोशन कालोनी, असावटी, जिला पलवल का रहने वाला हूं और शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरा बेटा राहुल और उसकी पत्नी सोनम मेरी व मेरी पत्नी की कोई बात नहीं मानते हैं। न ही हम लोगों की सेवा करते हैं। सोनम पुत्री स्व. किशनलाल निवासी रोशन कालोनी असावटी, जिला पलवल मुझे व मेरे परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती रहती है। इसलिए मैंने अपने बेटे राहुल व उसकी पत्नी सोनम को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। अब हमारा उन दोनों से कोई वास्ता नहीं है। वे चाहे जहां भी अपनी मर्जी से रहे। मैं उन्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। कोई भी व्यक्ति राहुल व उसकी पत्नी सोनम के साथ किसी तरह का लेन-देन करता है तो मेरी व मेरी पत्नी की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जय किशन पुत्र स्व. गिर्राज चंद